हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 78 लखनऊ, गुरुवार 30 अक्टूबर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक तरक्की की रीढ़ हैं एक्सप्रेसवे : मुख्यमंत्री

गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसम्बर तक पूरा करने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री ने दिए गति बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने की यूपीडा के परियोजनाओं की समीक्षा, कहा समयबध्दता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि एक्सप्रेसवे केवल सड़कों का जाल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक भविष्य की रीढ़ हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य दिसम्बर तक हर हाल में पूरा कराने के लक्ष्य के साथ तेज गति से आगे बढ़ाया जाए, ताकि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी अंचलों के बीच सहज कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा हो और कार्य की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता न हो। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार स्वरूप प्रस्तावित मेरठ–हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, नोएडा–जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट–रीवा लिंक एक्सप्रेसवे तथा प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे व विंध्य–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के रूट पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए एक्सप्रेसवे की योजना बनाते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और हाइवे नेटवर्क का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि दोहराव से बचते हुए राज्य में एकीकृत और समन्वित सड़क तंत्र विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े सभी नोड्स (लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट) में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रक्षा उद्योग से जोड़ना चाहिए, जिससे रोजगार सृजन के साथ ही क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। बैठक में बताया गया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक लगभग 30,819 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 5039 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। विभिन्न कंपनियों द्वारा कार्य प्रारंभ भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन नीति पर विशेष बल देते हुए कहा कि भूमि आवंटन के तीन वर्ष के भीतर यदि निवेशक द्वारा यथोचित उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसा आवंटन स्वतः निरस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि उपयोग की निगरानी की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए और निवेशक को केवल वास्तविक प्रगति की स्थिति में ही आगे की सुविधाएँ दी जाएँ। बैठक में यह भी बताया गया कि एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्कों में निवेश आकर्षित करने के लिए यूपीडा ने बिजली, जलापूर्ति, ट्रक टर्मिनल और हेल्थ–इमरजेंसी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु समयबद्ध योजना बनाई है।

आरजेडी नेताओं ने बिहार की छवि बिगाड़ी, बोले राजनाथ सिंह–नीतीश पर कोई नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का आरोप

एजेंसी

दरभंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और उसके नेतृत्व पर आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं ने बिहार की छवि न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में खराब की है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का नाम लिए बिना ही दरभंगा की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो दुख का विषय है। उनका कहना था, "मुद्दा साफ है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ढकेलना है।" सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था देश में 11वें स्थान से बढ़कर अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, "मोदी जी 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।" भाजपा के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी और शासन शैली की तारीफ करते हुए कहा, "20 वर्षों तक उन्होंने बिहार की सेवा की है।

क्या कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है?" उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बिहार को दो लाख करोड़ रुपये दिए, जबकि मोदी सरकार ने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए। उन्होंने कहा कि बिहार संस्कृति की भूमि है, किंतु पूर्ववर्ती संप्रग सरकार इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में विफल रही। सिंह ने राजद के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा अव्यावहारिक है। उन्होंने सवाल किया, "क्या बिना लोगों को धोखा दिए राजनीति नहीं की जा सकती?" उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जीडीपी 14 प्रतिशत है, जिससे यह देश में दूसरे स्थान पर है। "बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।" रक्षा मंत्री ने कहा कि राजग अपना घोषणा पत्र बुधवार को जारी करेगी और "हम उसके हर शब्द को जमीन पर उतारकर दिखाएंगे।

मुसलमानों को पार्टी से जोड़ो, मायावती का पदाधिकारियों को साफ संदेश, 2027 की चाभी हाथ से न जाए

संवाददाता

लखनऊ। अभी भले यूपी के चुनाव में एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है...लेकिन अभी से इसकी तैयारी में यूपी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने–अपने खेमों को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार जिस पार्टी को जो मजबूत नजर आ रहा है, उस कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। फिर चाहे मायावती हो या फिर अखिलेश, या फिर हो बीजेपी हर पार्टी अपने को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती अब मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने जा रही हैं। उन्होंने बुधवार को लखनऊ में प्रदेशभर से मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उनके साथ आकाश आनंद और राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी शामिल हुए, खबरों की माने तो बैठक में करीब 450 लोग हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई महिला पदाधिकारी भी मौजूद रही, बैठक में 75 जिला अध्यक्ष, 90 कोऑर्डिनेटर, 36 मुस्लिम भाईचारा कमेटी के अध्यक्ष और 36 बसपा के कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि पहले ये बैठक सिर्फ मुस्लिम भाईचारा कमेटी की थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, अब बसपा के जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, एक तरफ जहां मुस्लिमों वोटरों को कैसे अपनी तरफ किया जाए इसपर चर्चा हुई तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में होने वाली एसआईआर पर भी चर्चा की गई, बसपा के वोटरों का नाम कैसे वोटर लिस्ट में जुड़वाया जाए, पदाधिकारी को बूथ लेवल पर कैसे काम करें, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल, 25 अक्टूबर को ही मायावती ने प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा संगठन के मंडल प्रभारियों के नाम घोषित किए थे, अब वे सीधे इन्हें संगठनात्मक दिशा देने जा रही हैं, क्योंकि मायावती को भी अब समझ में आ गया है कि अगर यूपी की सत्ता की चाबी उन्हें दोबारा वापस चाहिए तो मुस्लम नाव पर सवार होना ही पड़ेगा। शायद यहीं वजह है कि मायावती की नजर अब मुस्लिम वोटरों पर टिक गई है। ताकी उनको अपनी तरफ कर सके। वैसे देखने होगा की आने वाले चुनाव में मायावती को इसका कितना फायदा मिलता है। बहरहाल जो भी हो लेकिन मायावती अपने दम से एक बार फिर सत्ता में आने को तैयार बैठी है।

गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा उपहार, गन्ना मूल्य 30 प्रति कुन्तल बढ़ा

पेराई सत्र 2025–26 में अगेती गन्ना 400, सामान्य 390 प्रति कुन्तल निर्धारित

गन्ना मूल्य वृध्दि से किसानों को होगा 3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं : लक्ष्मी नारायण चौधरी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार अब अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। इस वृद्धि से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा। योगी सरकार के कार्यकाल में यह चौथी बार है जब गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय न केवल गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा भी भरेगा। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। गन्ना हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है और हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य सही समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 2,90,225 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वर्ष 2007 से 2017 के बीच सपा और बसपा सरकारों में किसानों को कुल मात्र 1,47,346 करोड़ का भुगतान हुआ था। इस प्रकार सरकार ने मात्र साढ़े आठ वर्षों में पिछली सरकारों के मुकाबले 1,42,879 करोड़ अधिक भुगतान कर नया इतिहास रचा है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने–पौने दामों पर बेची गई थीं, वहीं सरकार के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुख नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है। पिछले आठ वर्षों में 4 नई चीनी मिलें स्थापित की गईं, 6 बंद मिलें पुनः शुरू की गईं और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ। इससे प्रदेश में 8 नई बड़ी मिलों के बराबर उत्पादन क्षमता में वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही, 2 मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे गन्ना क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को भी बल मिला है।

प्रदेश सरकार की अभिनव पहल 'स्मार्ट गन्ना किसान' प्रणाली के माध्यम से गन्ना क्षेत्रफल, सट्टा, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब किसानों को उनकी गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंचता है। इस प्रणाली को भारत सरकार ने मॉडल सिस्टम घोषित किया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। एथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि सरकार के प्रयासों से राज्य में एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है और आसवनियों की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो गई है। गन्ना क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है।

संक्षिप्त समाचार

चालू वित्त वर्ष में 7% की दर से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था : सीईए

एजेंसी

नयी दिल्ली। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया है और वित्त वर्ष 2025–26 में देश की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत तक पहुंचने की पूरी संभावना है। "भारत समुद्री सप्ताह" कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने हाल ही में भारत की साख बढ़ाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि मौजूदा नीतिगत रुख जारी रहा, तो भारत जल्द ही 'रेटिंग श्रेणी में शामिल हो सकता है। सीईए ने बताया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संयमित कदमों ने अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है, बावजूद इसके कि दुनिया अभी भी कई अनिश्चितताओं और शुल्क–आधारित तनावों से जूझ रही है। उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था की जुझारूपन ने भारत को वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिर बनाए रखा है।" नागेश्वरन ने यह भी बताया कि आयकर राहत और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने जैसे नीतिगत कदमों ने विकास को गति दी है।

लालू बेटे को मुख्यमंत्री, सोनिया बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, दोनों पद रिक्त नहीं : शाह

एजेंसी

दरभंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महागठबंधन को 'ठगबंधन करार दिया और कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन ये दोनों पद रिक्त नहीं हैं। उन्होंने दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जनता का आह्वान किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में दरभंगा की 10 में से 9 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खाते में गई थीं और इस बार वे सभी 10 सीटें राजग को दिलाएं। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में शाह ने महागठबंधन को 'ठगबंधन करार दिया और दावा किया कि लोकप्रिय कलाकार मैथिली ठाकुर भी चुनाव जीतेंगी। मैथिली अलीनगर से भाजपा की उम्मीदवार हैं। शाह ने कहा, "मैथिली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा राजग सरकार ने ही दिया। संविधान को भी मैथिली में उपलब्ध कराया गया है। मिथिला के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है। जहां–जहां माता सीता गईं, उन सभी स्थानों को राम सर्किट से जोड़ा जाएगा।" उन्होंने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा कि "कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाया लेकिन कांग्रेस और राजद ने इसका विरोध किया।" गृह मंत्री ने कहा, ''आतंकवादियों को पाकिस्तान के ठिकानों में मार गिराया गया और पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन क्या राजद की सरकार आएगी तो क्या वह पीएफआई के लोगों को जेल में रहने देगी? राजग किसी भी कीमत पर उन्हें बाहर नहीं आने देगा। शाह का कहना था कि जल्द ही दरभंगा में मेट्रो रेल संचालित होगी और राजग सरकार ने यहां एयरपोर्ट बनवाया है तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स का निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 8.52 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मखाना बोर्ड का गठन किया गया, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है। राजग प्रत्याशियों में युवाओं को तरजीह देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री। मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद खाली नहीं हैं। शाह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर 'चारा घोटाला और 'भूमि–के–बदले–नौकरी घोटाले में शामिल रहने के आरोप दोहराए तथा साथ ही, कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामलों में लिप्त होने का आरोप लगाया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने रच दिया इतिहास

राफेल विमान से भरी उड़ान, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

एजेंसी

अंबाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा के अंबाला में स्थित वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने भी इसी एयरबेस से एक अलग विमान में उड़ान भरी। राफेल विमान में चढ़ने से पहले राष्ट्रपति ने 'जी–सूट' पहना था। हाथ में हेलमेट लिए और धूप का चश्मा लगाए मुर्मू ने पायलट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। पूर्वाह्न 11.27 बजे विमान के उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने विमान के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आज सुबह वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने 8 अप्रैल, 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और वह ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी थीं। पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने क्रमशः 8 जून, 2006 और 25 नवंबर, 2009 को पुणे के पास लोहेगांव वायुसेना स्टेशन से सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान को सितंबर 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। पहले पांच राफेल विमानों को 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया था। ये विमान 27 जुलाई, 2020 को फ्रांस से यहां पहुंचे थे। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए सात मई को शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' में राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया था।

बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा– नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में

एजेंसी

मुजफ्फरपुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। इस सभा में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और इस गठबंधन के घटक दलों के कुछ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा, "बिहार में 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ भी नहीं मिले और अदाणी जी को एक–दो रुपये में जमीन दे दी जाए?

पीएम मोदी ने जापान की नव नियुक्त प्रधानमंत्री से की बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की नव नियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने विशेष रूप से भारत–जापान रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की।पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ताकाइची को पदभार ग्रहण करने पर बधाई और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत–जापान के बीच मजबूत संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। बाद में मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत–जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के अपने साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत–जापान के मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक वक्तव्य जारी कर बताया कि दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभाओं के आवागमन पर विशेष ध्यान देते हुए भारत–जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की।

संपादकीय

कसौटी पर एसआईआर

उम्मीद के अनुरूप चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस चरण में देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये केवल तीन माह का समय दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में एसआईआर पर लंबे समय से चले विवादों के मद्देनजर, इस प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दल शासित सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र से ऐसी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिये जरूरी है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अयोग्य मतदाता को हटाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर कोई विवाद नहीं माना जा सकता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही तत्काल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आगामी एसआईआर का लक्ष्य मतदाता सूचियों की लंबे समय से लंबित राष्ट्रव्यापी सफाई करना है। ऐसे व्यापक संशोधन देश में समय–समय पर हुए हैं और पिछला संशोधन दो दशक पहले हुआ था। जाहिर बात है कि इस लंबे अंतराल के दौरान मतदाता सूचियों में कई विसंगतियां और त्रुटियां उत्पन्न हो गई होंगी। आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के साथ–साथ पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव के लिये इन सूचियों का प्रमाणीकरण अपेक्षित है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष दलों की आशंकाओं की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही लोगों में लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के प्रति उत्साह बना रहना भी जरूरी है। दरअसल, कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों को आशंका है कि एसआईआर का इस्तेमाल अवैध मतदाताओं की पहचान की आड़ में लक्षित वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिये हो सकता है। वैसे बिहार में हुई कवायद के बाद ज्ञात नहीं है कि यह प्रक्रिया कितने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में सफल रही है। निस्संदेह, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा उचित प्रक्रिया–परिश्रम और जनता के विश्वास पर ही टिकी है। निर्विवाद रूप से देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था की ईमानदारी और निष्पक्षता दोषमुक्त होनी ही चाहिए। चुनाव आयोग को व्यापक सत्यापन, इस प्रक्रिया से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ विमर्श और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार को अक्षुण्ण बनाने हेतु एक ठोस निवारण तंत्र विकसित करने की जरूरत है। विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के कथित आरोपों का खंडन ठोस सबूतों के साथ किया जाना चाहिए। ताकि जनता में इस प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम रह सके। वैसे एसआईआर के दूसरे चरण का सकारात्मक पक्ष यह जरूर है कि आयोग ने प्रक्रिया के लिये पर्याप्त समय दिया है ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी के आक्षेपों से बचा जा सके। निश्चित रूप से आधार कार्ड को सहायक दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का लाभ प्रक्रिया के सरलीकरण में मिलेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियां इस दूसरे चरण की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का कार्य करेंगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दूसरे चरण में शामिल राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों को वैसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जैसी कि बिहार के लोगों में सामने आई थी। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि योग्य मतदाता न छूटे और कोई फर्जी मतदाता लिस्ट में शामिल न होने पाए। यहां उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में दूसरे चरण के दौरान मतदाता सूचियों को गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना है, उनमें से कुछ में अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी शामिल हैं। बहरहाल, कोशिश हो कि न ही जनता को परेशानी उठानी पड़े और न ही चुनाव कर्मियों में भ्रम जैसी स्थिति बनी रहे।

भाषा के पतन से लोकप्रियता के उत्कर्ष तक की कहानी

फूहड़ शब्दों का ग्लैमर और वर्चुअल समाज की विडंबना

— डॉ प्रियंका सौरभ

कुछ समय पहले तक मुझे यह गलतफहमी थी कि सोशल मीडिया पर केवल रील्स और वीडियोज़ में वल्गर या बेहूदा कंटेन्ट ही ज्यादा देखा जाता है। सोचती थी कि शायद यह दृश्य माध्यम का प्रभाव हैकृजहाँ चमक, शरीर और शोर ही बिकता है। पर हाल के दिनों में कुछ लम्बी पोस्टें पढ़कर भ्रम टूटा। अब केवल दृश्य नहीं, भाषा भी बिकाऊ हो गई है। फूहड़पन अब सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कलम की नोक पर भी नाच रहा है। इन पोस्टों में विषय तो वही पुराने और 'ट्रेंडिंग' हैंकृपुरुषों को कोसना, संबंधों में स्त्री की पीड़ा या समाज की संकीर्णता। पर इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन विचारों को जिस भाषा में व्यक्त किया जा रहा है, वह भाषा नहीं, गाली का उत्सव लगती है। लाइक्स और कमेंट्स की बरसात होती है, और भीड़ ताली बजाती हैकृ मानो फूहड़ता अब किसी नई 'साहित्यिक विधा' का नाम बन चुकी हो। कभी कहा जाता था कि लिखना, दिखने से कठिन होता है। लिखना मतलब सोचना, मनन करना, किसी विषय पर आत्मा से उतरकर बोलना। शब्द कभी भीड़ को लुभाने का नहीं, समाज को सजग करने का माध्यम होते थे। लेकिन आज इस संतुलन को एक नई भूख ने निगल लिया हैकृलोकप्रियता की भूख। अब जो सबसे तेज़, सबसे तीखा और सबसे विवादित लिखेगा, वही सबसे ज्यादा देखा जाएगा। 'क्लिक' और 'कमेंट' की इस दौड़ ने शब्दों की गरिमा को लगभग निचोड़ कर रख दिया है। अब भाषा का अर्थ अभिव्यक्ति नहीं, उत्तेजना रह गया है। और यह प्रवृत्ति केवल अनपढ़ या असंवेदनशील वर्ग तक सीमित नहींकृकई बार वही लोग, जो समाज में सुधार, परिवार में संस्कार और रिश्तों में मधुरता की बातें करते हैं, इन पोस्टों पर टूट पड़ते हैं। वे न केवल इन्हें पढ़ते हैं, बल्कि 'लाइक', 'हार्ट' और 'फायर इमोजी' भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैंकृ जैसे यह कोई सांस्कृतिक आंदोलन हो। यह सवाल सबसे ज्यादा चुभता हैकृआखिर इस फूहड़ता में आकर्षण क्या है? क्या लोग वास्तव में इन विचारों से सहमत हैं, या बस भीड़ में शामिल हो जाने की मजबूरी है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोशल मीडिया ने व्यक्ति को 'अदृश्य पहचान' दी है। अब वह जो कहना, करना या दिखाना असल ज़िंदगी में नहीं कर सकता, उसे वह वर्चुअल दुनिया में निर्भीक होकर कर सकता है। यह आज़ादी धीरे–धीरे अराजकता में बदल गई है। भाषा की मर्यादा, सामाजिक संवेदना और दूसरों की गरिमाकृ सब पर खुली छूट मिल गई है। किसी का अपमान करना, समूहों को उकसाना, व्यंग्य में विष घोलनाकृयह सब अब 'क्रिएटिविटी' कहलाता है। फूहड़ भाषा को 'निर्भीक अभिव्यक्ति' बताया जा रहा है, और सभ्य संवाद को 'पाखंड'। विचारों की जगह शब्दों का शोर छा गया है। विडंबना यह है कि यही समाज घर में बच्चों को मर्यादा, संस्कार और आदर का पाठ पढ़ाता है, मगर वर्चुअल मंच पर वही लोग अपशब्दों की पोस्ट पर हंसते हुए इमोजी भेजते हैं। यानी हमारी वास्तविक और वर्चुअल नैतिकता में ज़मीन–आसमान का अंतर है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने हमें संवाद का अवसर दिया था, पर हम उसे विवाद का अखाड़ा बना बैठे। जहाँ पहले विचारों की टकराहट होती थी, वहाँ अब शब्दों की लाठियाँ चलती हैं। यह प्रवृत्ति केवल भाषा की समस्या नहीं, सामाजिक संस्कृति के क्षरण का संकेत है। क्योंकि जब शब्द दूषित होते हैं, तो विचार भी विकृत हो जाते हैं। और जब विचार विकृत होते हैं, तो समाज में असहिष्णुता पनपती है। आज यही हो रहा हैकृहर वर्ग अपने पक्ष को 'एकमात्र सत्य' मानने लगा है, और जो असहमत है, उसके लिए अपशब्द तैयार रखे हैं। कला, चाहे लेखन हो या अभिनयकृसमाज से संवाद का माध्यम है। लेकिन संवाद और प्रहार में फर्क होता है। जो शब्द किसी की गरिमा को चोट पहुँचाएँ, वे अभिव्यक्ति नहीं, आक्रोश का प्रदर्शन हैं। और जब यह आक्रोश लोकप्रियता के रास्ते का शॉर्टकट बन जाए, तब समाज को आत्ममंथन करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम लोकप्रियता और गरिमा के बीच अंतर समझें। लिखना सिर्फ 'लोग क्या कहेंगे' के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि 'मैं क्या कहना चाहता हूँ' के लिए होना चाहिए। सच्चा लेखक भीड़ से नहीं, विवेक से संवाद करता है। लेकिन अफसोस, आज सोशल मीडिया ने साहित्य को मनोरंजन और विचार को व्यापार बना दिया है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयरकृकेवल एक बटन नहीं, एक नैतिक निर्णय है। जब हम किसी फूहड़ पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अनजाने में उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम तो वही दिखाता है जो अधिक देखा जाता है। इसलिए असभ्य कंटेन्ट तभी बढ़ता है जब हम उसे बढ़ाते हैं। दर्शक अगर जिम्मेदार बन जाएँ, तो निर्माता भी सुधरने को मजबूर होंगे। संवेदनशील और सुसंस्कृत समाज वही होता है जहाँ लोकप्रियता का मापदंड शब्दों की गरिमा हो, न कि शब्दों की उत्तेजना। सोशल मीडिया अब किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का दर्पण है। यहाँ जो लिखा, कहा और साझा किया जा रहा हैकृ वही हमारी सामूहिक सोच बन रहा है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में शालीनता और संवेदना बनी रहे, तो हमें वर्चुअल व्यवहार में भी वही अनुशासन अपनाना होगा जो वास्तविक जीवन में अपनाते हैं। फूहड़ शब्दों की लोकप्रियता अल्पकालिक है, पर उनका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक। विचारों की ताकत शब्दों की मर्यादा में ही बसती है, न कि उनकी अशालीनता में। इसलिए अब वक्त है कि हम ठहरकर सोचेंकृक्या हम वाकई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बस असभ्यता की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं? और अगर जवाब दूसरा है, तो हमें याद रखना चाहिएकृ सभ्यता की पहली पहचान भाषा होती है, और जब भाषा गिरती है, तो समाज भी गिर जाता है।

देश का भविष्य अल्प-पोषित ना हो

—संजीव ठाकुर

बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं, क्योंकि वही आने वाले कल के नागरिक, निर्माता और राष्ट्र के सशक्त स्तंभ बनते हैं। किंतु यदि वही बच्चे कमजोर, कुपोषित और अविकसित रह जाएँ, तो सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना मात्र भ्रम बनकर रह जाएगी। आज भारत में बच्चों का कुपोषण और बाल विवाह जैसी सामाजिक विसंगतियाँ देश के विकास पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़े कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग 18.7: बच्चे गंभीर रूप से "वेस्टिंग" यानी तीव्र कुपोषण के शिकार हैं, जो विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है। यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के लगभग हर चौथे बच्चे को गंभीर खाद्य गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि 25: बच्चों को विविधा और पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे न केवल कमजोर शरीर लेकर बड़े होते हैं बल्कि मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं। यह स्थिति भविष्य के नागरिकों की गुणवत्ता और देश की कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित करती है। कुपोषण की जड़ें केवल भोजन की कमी में नहीं, बल्कि असमान संसाधन वितरण, गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी–सामाजिक तंत्र की कमजोर समन्वय नीति में भी छिपी हैं। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान, मिड–डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों और मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं, परंतु परिणाम अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे। सवाल यह उठता है कि जब अरबों रुपये स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर भी बच्चे क्यों कुपोषित हैं? जवाब स्पष्ट है कृ योजनाओं की जमीनी निगरानी और जनसहभागिता का अभाव। कुपोषण के समानांतर बाल विवाह की समस्या भी उतनी ही गंभीर है। 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद, यूनिसेफ के अनुसार भारत में आज भी लगभग 23: महिलाएँ 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह के बंधान में बंध जाती हैं। दक्षिण के शिक्षित राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु भी इस सूची में शीर्ष पर हैं। यह विडंबना दर्शाती है कि केवल शिक्षा की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समाज में मानसिक–सांस्कृतिक जागरूकता आवश्यक है। बाल विवाह न केवल एक लड़की की शिक्षा और आत्मनिर्भरता छीन लेता है, बल्कि उसके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बाधित करता है। गर्भधारण के दौरान कुपोषण और स्वास्थ्य–जोखिम बढ़ जाता है, जो अगले पीढ़ी तक दुर्बलता को पहुँचाता है। सामाजिक संगठनों और गैर–सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। "अक्षय पात्र फाउंडेशन" जैसे संगठनों ने स्कूल मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया है। "सेव द चिल्ड्रन", "स्माइल फाउंडेशन" और "चाइल्डलाइन" जैसी संस्थाएँ पोषण, शिक्षा और बाल–सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रही हैं।

किंतु केवल कुछ संगठनों के प्रयास पर्याप्त नहीं कृ आवश्यकता है एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की, जहाँ हर नागरिक अपनी भूमिका को समझे और समाज अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे। कुपोषण और बाल विवाह की समस्या एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी है। जब कोई बच्ची अल्पायु में विवाह करती है, तो उसका शारीरिक विकास अधूरा रहता है, गर्भावस्था में उसे उचित पोषण नहीं मिल पाता और जन्म लेने वाला बच्चा भी कमजोर होता है। इस प्रकार कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। इसे तोड़ने के लिए सरकार, समाज और नागरिककृसभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। आज समय है कि पोषण और शिक्षा को केवल सरकारी योजनाओं का हिस्सा न मानकर सामाजिक दायित्व बनाया जाए। स्कूलों, पंचायतों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण–जागरूकता के केंद्रों में बदला जाए। स्थानीय स्तर पर पोषण–समिति बनाकर बच्चों के आहार, स्वास्थ्य जांच और विकास की नियमित निगरानी की जाए। माता–पिता को भी यह सिखाना होगा कि बच्चे को केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं, बल्कि पौष्टिक आहार देना आवश्यक है। भारत के लिए यह चिंताजनक है कि वैश्विक भूख सूचकांक में 2024 में वह 125 देशों में 111वें स्थान पर पहुँच गया, जबकि पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल इससे आगे हैं। यह संकेत है कि यदि हमने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया, तो आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक स्वास्थ्य दरकता जाएगा। समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

छठ पर्व में राजनीति की घुसपैठ

पूर्वांचलियों के लिए महापर्व समान छठ पूजा चार दिनों की धूमधाम के साथ संपन्न हुई। बीते कुछ बरसों में बिहार और उत्तरप्रदेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में भी छठ की धूम दिखने लगी है, क्योंकि इन राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार, शिक्षा या व्यवसाय के लिए पूर्वांचल से लोग आकर बस गए हैं। छठ पर्व में 36 घंटे का कठिन व्रत किया जाता है और व्रतियों के अलावा पूरा परिवार स्वच्छता पर खास ध्यान देता है। इस पर्व में नदियों की महत्ता, खेती का सम्मान नए सिरे से रेखांकित किया जाता है। छठ का प्रसाद घर पर ही बनता है, और इसी का वितरण सबमें होता है। अर्घ्य देने के वक्त सूप में गन्ना, मूली, कंद, सेब, केले जैसे मौसमी फल होते हैं। इस लिहाज से देखें तो दीपावली, करवा चौथ, क्रिसमस आदि के विपरीत छठ पर्व ने अब तक बाजार को अनाधिकार प्रवेश से रोक कर रखा है। हालांकि राजनीति ने लोक आस्था के इस पर्व में अपनी घुसपैठ कर ही ली है। हिंदी पट्टी पर भाजपा धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए ही अपना दबदबा बढ़ा पाई है। पहले ये भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई होती थीं, अब मंदिर बन गया है तो भाजपा ने अपनी रणनीति में हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों को सियासत का जरिया बना लिया है। नवरात्रि पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व्रत और कन्यापूजा करते दिखते हैं। रामलीलाओं का हिस्सा बनते हैं। दीपावली पर अयोध्या में दीए जलाने का रिकार्ड बनने लगा है और अब दिल्ली जीतने के बाद यहां भी यह सिलसिला शुरु हो गया है। छठ पूजा पर भी दिल्ली में हलचल रहती ही थी, लेकिन इस बार बिहार चुनाव के कारण भाजपा ने मानो इसे अपना राजनैतिक पर्व मनाने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अर्घ्य देते नजर आईं, ताकि पूर्वांचलियों से निकटता दिखा सकें। इस बार तो राष्ट्रपति मुर्मू के अर्घ्य देने की तस्वीरें भी सामने आईं। बिहार के नेताओं के घरों पर शुरु से छठ पूजा होती रही है। लेकिन बिहार चुनावों के कारण सोशल मीडिया पर सभी ने छठ पूजा की खूब सारी तस्वीरें डालीं, ताकि जनता को बताया जा सके कि छठी मैया से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बार तस्वीरों की इस प्रतियोगिता में चूक गए। उनकी तैयारी तो पूरी थी कि दिल्ली के वासुदेव घाट पर जाकर अर्घ्य वे दें और फिर उन तस्वीरों को जनता तक पहुंचाएं। भाजपा समर्थित मीडिया के कुछ एंकर्स भी वासुदेव घाट जाकर, रेखा गुप्ता का साक्षात्कार कर यह माहौल बना चुके थे कि भाजपा सरकार के आते ही यमुना नदी साफ हो गई है।

राशिफल

मेष :– भावुकता वश संबंधों में भावनात्मक शोषण की आशंका है। पूर्वाग्रह वश अपने निकटस्थ सम्बन्धों के बारे में गलत धारणा पालना ठीक नहीं। सम्बन्धों की मधुरता हेतु आपस में विास कायम करें।

बृषभ :– व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिश्रम से आर्थिक लाभ के योग हैं। अत्यधिक भावुकता से भावनात्मक शोषण की भी आशंका है। भौतिक जगत से प्रभावित मन भविष्य को लेकर चिन्तित होगा।

मिथुन :– किसी अचल सम्पत्ति क्रय हेतु प्रयत्न तीव्र। अपने भाग्य को कोसना छोड़ अपने समय का सकारात्मक दिशा में लगावें। मान–प्रतिष्ठा में बृद्धि तो होगी परन्तु इससे अभिमानी न बनें।

कर्क :– समाजिक मान–सम्मान व वर्चस्व में बृद्धि होगी। व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिभा में निखार आयेगा। आपके स्थितियों में आकस्मिक सुधार के आसार बन रहें। कल्पनाएं साकार होती नजर आएंगी।

सिंह :– नये कायरे में पूंजी निवेश हेतु धनाभाव अवरोधक होगा। आपमें दूसरों को आकर्षित करने की अभूतपूर्व क्षमता है इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी।

कन्या :– रोजगार के क्षेत्र में किये गये कर्म का फल सफलता का आगाज कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में परिश्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी। परिजनों की सुख–सुविधा के प्रति मन चिन्तित होगा।

तुला :– प्रणय सम्बन्ध में केन्द्रित मन प्रियतम से मिलने के लिऐ ब्याकुल होगा। किसी खास मुद्दे को लेकर परिजनों के मतभेद का सामना करना पड़ेगा। प्रयासरत क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी।

वृश्चिक :– अच्छे अवसरों का लाभ उठानें में सक्षम बनें। जीवन में नीरसता को कम करने के लिए मन को सकारात्मक दिशा देवें। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता से मन उत्साहित होगा।

धनु :– भावुकतावश किसी सम्बन्धी की बातें मन को कष्ट पहुचा सकती हैं। अपने अन्दर नए उर्जा की अनुभूति करेंगे। लेकिन बिगड़े हुए सम्बन्धों को सुधारने की चेष्ठा करें। कार्य क्षेत्र में नये आसारों से उत्साहित होंगे।

मकर :– उच्छृंखल व मजाकिया स्वभाव आस–पास के वातावरण में महत्ता तो बढ़ाएगा। रोजगार में अपनी स्थिति को लेकर मन में हीनता का वाश होगा। महत्वपूर्ण पारिवारिक दायित्वों के पूर्ति के आसार बनेंगे।

कुंभ :– परिवार में किसी की अस्वस्थता से मन चिन्तित होगा। परिवारिक जिम्मेदारियां मन को बोझिल करेंगी। कोई अवरोधित काम के प्रति मन विशेष रूप से चिन्तित होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में प्रयत्न सार्थक होगा।

मीनः– सरल व मिलनसार स्वभाव से संबंधों में लोकप्रिय होंगे। भौतिक सुख–साधनों की लालसा में व्यय के योग हैं। जीविका क्षेत्र में परिश्रम सार्थक होगा। भावना प्रधान मन जल्द ही दूसरों से प्रभावित हो जाता है।

आरएसएस एक सांस्कृतिक आधिपत्यवादी संस्था कैसे बना

—आनंद तेलतुंबडे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातिवाद को बढ़ावा देने और हाशिये पर पड़े लोगों को बाहर रखने के बावजूद दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिविल सोसाइटी संगठन बन गया है। आरएसएस ने एक विशाल कैडर नेटवर्क और संघ परिवार इकोसिस्टम बनाया, जिससे उसे भाजपा के जरिए जमीनी स्तर पर और राजनीतिक नियंत्रण मिला। सामाजिक कार्य, दिखावटी समावेश और संस्थागत कब्जे के जरिए, इसने हिंदू एकता की आड़ में ब्राह्मणवादी विचारधारा फैलाई। राज्य की नाकामियों और सांप्रदायिक डर का फायदा उठाकर, आरएसएस लोकतंत्र का इस्तेमाल सत्तावादी और बहिष्कारवादी शक्ति को मजबूत करने के लिए करता है। केशव बलिराम हेडगेवार, जो एक देशस्थ ब्राह्मण थे, द्वारा 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), जो भारत की आबादी के मुश्किल से 3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ब्राह्मणवादी संगठन था, एक चौंकाने वाला विरोधाभास दिखाता है। औपनिवेशिक शक्ति के साथ सहयोग, संविधान का विरोध, जातिवाद को बढ़ावा देने और हाशिये पर पड़े लोगों को बाहर रखने के अपने इतिहास के बावजूद, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सिविल सोसाइटी संगठन बन गया है, जो बीजेपी के जरिए जबरदस्त राजनीतिक नियंत्रण रखता है। इस विरोधाभास को समझाने के लिए आरएसएस की रणनीतिक समझ, संरचनात्मक फायदे और वैचारिक हेरफेर को समझना जरूरी है, जिसने इसे बहु–जातीय लोकतंत्र में ब्राह्मणवादी वर्चस्व बनाए रखने में सक्षम बनाया है। आरएसएस की मुख्य ताकत उसकी असाधारण संगठनात्मक संरचना में निहित है, जिसे लगभग एक सदी में बेहतर बनाया गया है। शाखा प्रणाली रोजाना की सभाओं का एक व्यापक नेटवर्क बनाती है जहाँ सदस्य शारीरिक व्यायाम, वैचारिक प्रशिक्षण और समुदाय निर्माण में भाग लेते हैं। यह पदानुक्रमित संरचना–स्थानीय शाखाओं से लेकर क्षेत्रीय प्रांतों (जोन) से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक–वैचारिक एकरूपता, अनुशासन और तेजी से लामबंदी की क्षमता सुनिश्चित करती है जिसकी बराबरी भारत में कोई अन्य सिविल सोसाइटी संगठन नहीं कर सकता। आरएसएस तुरंत राजनीतिक लामबंदी के बजाय धैर्यपूर्वक, लंबे समय तक कैडर बनाने के जरिए काम करता है। सदस्यों को बचपन से ही रोजाना की शाखाओं के जरिए दीक्षित किया जाता है, जिससे जीवन भर की प्रतिबद्धता और वैचारिक वफादारी पैदा होती है। यह अनुशासित स्वयंसेवक आधार, जिसकी संख्या लाखों में होने का अनुमान है, राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी के लिए एक बेजोड़ मानव संसाधन प्रदान करता है। संगठन की पदानुक्रमित अनुशासन बनाए रखने की क्षमता, जबकि स्वैच्छिक भागीदारी के जरिए काम करने का दिखावा करते हुए, केंद्रीकृत ब्राह्मणवादी नियंत्रण बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक जमीनी समर्थन का भ्रम पैदा करती है। आरएसएस की खासियत यह है कि उसने सहयोगी संगठनों (संघ परिवार) का एक बड़ा परिवार बनाया है जो भारतीय समाज के लगभग हर सेक्टर में फैला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (छात्र विंग), (लेबर विंग), भारतीय किसान संघ (किसान), वनवासी कल्याण आश्रम (आदिवासी), और दर्जनों अन्य संगठनों के जरिए, आरएसएस केंद्रीकृत वैचारिक नियंत्रण बनाए रखते हुए अलग–अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दिखावा करता है। यह मल्टी–ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा आरएसएस को यह दावा करने की अनुमति देता है कि वह समाज के सभी वर्गों की सेवा कर रहा है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि नेतृत्व और वैचारिक दिशा मजबूती से ब्राह्मणों के हाथों में रहे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राजनीतिक सफलता दिखाती है कि यह संगठनात्मक इकोसिस्टम चुनावी प्रभुत्व में कैसे बदलता है। आरएसएस, बीजेपी को एक बेजोड़ संगठनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैडर बेस और वैचारिक वैधता प्रदान करता है, जिससे एक सहजीवी संबंध बनता है जहाँ राजनीतिक शक्ति संगठनात्मक विस्तार को मजबूत करती है और इसके विपरीत भी। खंडित विपक्षी पार्टियों पर यह संरचनात्मक लाभ आरएसएस–बीजेपी की लगातार चुनावी सफलता को समझाने में मदद करता है, इसके बावजूद कि उनकी नीतियां अक्सर उन्हीं समुदायों के भौतिक हितों को नुकसान पहुंचाती हैं जो उन्हें वोट देते हैं। शायद आरएसएस की सबसे प्रभावी रणनीति एक एकीकृत हिंदू पहचान बनाने की उसकी क्षमता रही है जो बाहरी दुश्मन बनाकर जातिगत विभाजनों से ऊपर उठती है – मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई, लेकिन राष्ट्र–विरोधी तत्व, पश्चिमी संस्कृति, और विभिन्न अन्य गढ़े हुए खतरे भी। इन गढ़े हुए खतरों के खिलाफ हिंदू समाज के रक्षक के रूप में खुद को पेश करके, आरएसएस दलितों, आदिवासियों और व्ठे को अपनी जातिगत पहचान और भौतिक हितों को एक काल्पनिक धार्मिक एकजुटता के अधीन करने के लिए मनाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की यह रणनीति कई काम करती है। पहला, यह लोकप्रिय गुस्से को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर केंद्रित करके जातिगत उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से ध्यान हटाती है। दूसरा, यह हिंदू पहचान में भावनात्मक निवेश पैदा करती है जिसका आरएसएस विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने और रक्षा करने का दावा करता है। तीसरा, यह आरएसएस के किसी भी विरोध को हिंदू धर्म के ही विरोध के रूप में पेश करता है, जिससे आलोचकों को बदनाम किया जाता है। लगातार संकट पैदा करनाकृचाहे वह गाय संरक्षण अभियानों, लव जिहाद की कहानियों, या धर्मांतरण विरोधी कानूनों के माध्यम से होकृसमुदायों को धार्मिक पहचान के इर्द–गिर्द लामबंद रखता है, जबकि आरएसएस के ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बनाए रखने के असली एजेंडे को छिपाता है। आरएसएस ने रणनीतिक रूप से सामाजिक सेवा गतिविधियों में निवेश किया हैकृस्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, आपदा राहत अभियान और सामुदायिक विकास कार्यक्रमकृजो सद्भावना पैदा करते हैं और साथ ही वैचारिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी काम करते हैं। ये सेवा गतिविधियाँ विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों और हाशिए पर पड़े समुदायों में प्रभावी हैं जहाँ राज्य सेवाएँ अनुपस्थित या अपर्याप्त हैं। राज्य की उपेक्षा से पैदा हुए खालीपन को भरकर, वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती जैसे आरएसएस से जुड़े संगठन निर्भरता के रिश्ते बनाते हैं, साथ ही विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं वाले समुदायों पर ब्राह्मणवादी हिंदू सांस्कृतिक मानदंडों को थोपते हैं। यह सामाजिक सेवा कार्य दोहरा उद्देश्य पूरा करता है, यह आरएसएस को एक परोपकारी संगठन के रूप में वैधता प्रदान करता है, जबकि वैचारिक रूपांतरण और सांस्कृतिक आत्मसात के अवसर भी प्रदान करता है। आदिवासी समुदायों को उनकी स्वदेशी प्रथाओं को छोड़ने और शुद्ध ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को अपनाने के लिए सिखाया जाता है। दलित समुदायों को भौतिक सहायता मिलती है, जबकि उन्हें हिंदू धर्म के भीतर अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार आरएसएस सामाजिक सेवा को सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के एक तंत्र में बदल देता है, जिसका उपयोग तत्काल भौतिक लाभों का उपयोग करके दीर्घकालिक वैचारिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए किया जाता है। आरएसएस ब्राह्मणवादी नियंत्रण बनाए रखते हुए समावेशिता की छवि पेश करने में तेजी से परिष्कृत हो गया है। ओबीसी, दलित और आदिवासी नेताओं को प्रमुख पदों पर पदोन्नत करके, आरएसएस यह भ्रम पैदा करता है कि उसने अपनी ब्राह्मणवादी उत्पत्ति को पार कर लिया है। प्रतीकात्मक समावेश की यह रणनीति विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि यह हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आकांक्षी रोल मॉडल प्रदान करती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि वास्तविक शक्ति ब्राह्मणवादी हाथों में केंद्रित रहे। हालांकि, संरचनात्मक विश्लेषण इस समावेशिता की खोखलेपन को उजागर करता है। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्वकृसरसंघचालक और मुख्य निर्णय लेने वाले निकायकृपूरी तरह से ब्राह्मणवादी बना हुआ है। किसी भी दलित या आदिवासी ने कभी भी शीर्ष पद नहीं संभाला है, और न ही निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। संगठन के वैचारिक ग्रंथ ब्राह्मणवादी वर्चस्व और वर्ण व्यवस्था का महिमामंडन करते रहते हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधियों का तब सम्मान किया जाता है।

लखनऊ में होने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो, रणभूमि 1.0 क्लैश ऑफ बाहुबलीज

'यूपी दिवस के दिन लखनऊ में लगेगा इंटरनेशनल रेसलर्स का जमावड़ा'

संवाददाता

लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ अब एक ऐतिहासिक खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। पहली बार भारत में इतने बड़े स्तर पर अंतरराष्ट्रीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो आयोजित किया जा रहा है – जिसका नाम है "रणभूमि 1.0 : क्लैश ऑफ बाहुबलीज", जिसमे विदेश से आये प्रतिष्ठित फ्रीस्टाइल रेसलर्स अपना जौहर दिखायेंगे,जो 24 जनवरी 2026 को के. डी. सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की खेल भावना और नई ऊर्जा को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है। अब यूपी और खासतौर पर लखनऊ, खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इसी दिशा में "रणभूमि 1.0" रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत (WWB) खेल और मनोरंजन का एक शानदार संगम होगा।'द क्लैश ऑफ बाहुबलीज में दुनिया के दिग्गज पहलवान, फ्रीस्टाइल रेसलिंग सुपरस्टार्स हिस्सा लेने आ रहे हैं। जिनमें अब तक तय हुए पहलवानों में शामिल हैं– क्रिस मास्टर्स (अमेरिका), जो ई. लीजेंड (कनाडा), ग्रेट अलोफा (समोआ अमेरिका), कार्लिटो (प्यूर्टो रिको), जुबरी (दक्षिण अफ्रीका), काउबॉय जे. स्टॉर्म (अमेरिका), टी.जे. ट्रेमर (दक्षिण अफ्रीका)और कई अन्य विदेशी स्टार पहलवान।'भारत की ओर से टाइगर राष्टा और बारूद जैसे नामी पहलवान इस अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उतरेंगे, जो भारत की ताकत और परंपरा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन की औपचारिक घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें मुख्य रूप से 'राज सिंह, संस्थापक – रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत ६ बीजर बॉन्जर वर्ल्ड, मार्क बील, चेयरमैन – WWP/WA' (दक्षिण अफ्रीका), टाइगर राष्टा, वर्ल्ड हैवीवेट चौंपियन, अनिता सिंह, सह–संस्थापक – रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत बीजर बॉन्जर वर्ल्ड, हसन याकूब, को–चेयरमैन –ASSOCHAM' मौजूद रहे।'राज सिंह, रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत और बीजर बॉन्जर वर्ल्ड के संस्थापक ने इस खास मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि' "यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि भारत के सबसे पुराने और प्रिय खेल – कुश्ती कृ को नए रूप में पुनर्जीवित करने का मिशन है। हमारे पूर्वजों की विरासत को आधुनिक मंच पर लाना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। अब वक्त है कि भारत अपने बाहुबली योद्धाओं के दम पर दुनिया को दिखाए कि असली ताकत क्या होती है।"राज सिंह एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और पहले पीढ़ी के उद्यमी हैं, जिन्होंने फ्रीस्टाइल रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत और क्लैश ऑफ बाहुबलीश की शुरुआत की है।'वहीं, मार्क बील, जो दक्षिण अफ्रीका के WWP/WA' के चेयरमैन' हैं और पिछले 40 वर्षों में 50 से अधिक देशों में हजारों फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो आयोजित कर चुके हैं, ने कहा "मैं हमेशा से भारत आकर फ्रीस्टाइल रेसलिंग कराना चाहता था। भारत की संस्कृति, ताकत और जुनून दुनिया को प्रेरित करेगा। यह साझेदारी भारत और दुनिया के रेसलिंग जगत को जोड़ने का सेतु बनेगी।"उन्होंने भारत के टाइगर राष्टा, हिमाचल प्रदेश के विश्व हैवीवेट चौंपियन की भी सराहना की, जो भारत के गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं।इस कार्यक्रम के पीछे राज सिंह और अनिता सिंह के का एकमात्र उद्देश्य भारत की प्राचीन कुश्ती परंपरा को पुनर्जीवित करना है।एवं उन भारतीय पहलवानों को मंच देना, जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिले हैं। साथ ही लखनऊ में फ्रीस्टाइल प्रोफेशनल रेसलिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का भी विचार है, ताकि देशभर के युवा नई दिशा पा सकें।"रणभूमि 1.0 रू क्लैश ऑफ बाहुबलीज" सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि एक अभियान है – भारत की ताकत, परंपरा और खेल भावना को फिर से विश्व मंच पर लाने का।अंतरराष्ट्रीय सितारे, भारतीय योद्धा और उत्साह से भरा माहौल कृ यह आयोजन लखनऊ को एक बार फिर देश का गौरव बना देगा। साथ ही दुनिया के पहलवानों को भारत के बाहुबलियों के साथ भारत की मिट्टी पर मुकाबला करने के लिए आमंत्रित करना भी अपने आप में खास होगा।

मोहनलालगंज व गोसाईंगंज में 06 अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर

– एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन–1 एवं जोन–2 की टीम ने की कार्रवाई

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को प्रवर्तन टीम ने मोहनलालगंज व गोसाईंगंज क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 06 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। प्रवर्तन जोन–1 की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया कि अजय विक्रम सिंह, राजकुमार व अन्य द्वारा गोसाईंगंज में सुलतानपुर रोड पर ग्राम–सलौली में 02 अलग–अलग स्थानों पर लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। एलडीए से ले–आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करायी गयी। इस दौरान निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन जोन–2 के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि संतराम, संजय यादव, रंजीत व अन्य द्वारा मोहनलालगंज में न्यू जेल रोड पर स्थित ग्राम–मऊ में 04 अलग–अलग स्थानों पर लगभग 36 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लाटिंग को अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को बंधी उम्मीद

संवाददाता

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरि किशोर तिवारी व महामंत्री शिवबरन सिंह यादव द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से केन्द्रीय कैबीनेट द्वारा आठवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना का स्वागत करते हुए विलम्ब ले लिया जाने वाला सही कदम बताया है। कर्मचारी नेता इं. हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि जनवरी 2025 में केन्द्र द्वारा के वतन आयोग के गठन निर्णय लिया गया था किन्तु लगभग 10 आह बाद उसके गठन की अधिसूचना तथा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्रीय कैबिनेट के निर्णय की सूचना के अनुसार यह आयोग सिर्फ केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तो के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा। जिसकी समय सीमा 18 माह होगी। हालाकि यह जनवरी 2026 से प्रभावी माना जायेगा। किन्तु इनमें केन्द्रीय कर्मचारियो के साथ पेंशनर्स का उल्लेख नही है, यह पूर्व के नोटीफिकेशन के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है। जिसके द्वारा दिसम्बर 2025 के उपरान्त अर्थात आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं दिये जाने की आशंका साबित हो रही है। कर्मचारी नेताओ ने केन्द्रीय सरकार से वेतन आयोग को पेंशनर्स से सम्बंधित संस्तुति को भी शामिल किये जाने की मांग की गई है।श्री तिवारी और श्री यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि आजाद भारत के बाद से कभी भी ऐसा नही हुआ है कि सेवारत कर्मचारियो, सेवानिवृत्त के लिए वेतन आयोगों (केन्द्र व राज्यो) द्वारा एक साथ विचारण नही किया गया हो। किन्तु ऐसा नही किया जाना एक बडे आन्दोलन के रूप में देखा जा सकता है।केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कें उपरान्त केन्द्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संगठनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि का. शिवगोपाल मिश्रा के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग के समक्ष टर्म्स आफ रेफरेन्स प्रेषित करते हुए केन्द्रीय वेतन आयोग से विचार किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए आयोग को विचारण करने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन ऐसा नही किए जाने से राज्य कर्मचारी अपने हक से वंचित रह जाएगें। परिषद के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नरेश कुमार ने आठवे वेतन आयोग के गठनका स्वागत करते हुए कहा कि महंगाई के दृष्टिगत अपनी रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करने की मांग की गई है। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने पूर्व की भांति जनवरी 2026 जब तक वेतन आयोग की संस्तुतियो को लागू किया जाय तब तक अन्तरिम राहत लागू दिए जाने की मांग की है। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमकुमार सिंह, संयुक्त मंत्री अविनाश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, संयुक्त मंत्री विवेक कुमार उप महामंत्री अमिता त्रिपाठी, अशोक कुमार सिंह, सुभाषचन्द्र तिवारी, इं. डी. पी. सिंह, इं. श्रवण कुमार कुमार यादव,इं.राम सुरेश सिंह, पी.के. मिश्रा, अरूण कुमार सिंह आदि ने केन्द्रीय चुनाव आयोग से शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है।

संक्षिप्त

महापौर ने जनता दरबार में सुनीं 200 से अधिक शिकायतें

संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम मुख्यालय में बुधवार को आयोजित जनता दरबार में महापौर सुषमा खर्कवाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश जारी किए। इस मौके पर माननीय कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष श्रीमती चरणजीत गांधी जी एवं माननीय पार्षदगण भी उपस्थित रहे। इस दौरान नगर निगम से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल के समक्ष लगभग 200 से अधिक नागरिकों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं। इनमें अतिक्रमण, साफ–सफाई, पेयजल आपूर्ति, मार्गप्रकाश (स्ट्रीट लाइट), टैक्स व भवन संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं। महापौर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही तलब किया और आवश्यक निर्देश दिए। जनता दरबार में कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिनमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी। महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों का तीन कार्य दिवस के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान में लापरवाही या देरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान साउथ सिटी क्षेत्र से 50 से अधिक महिलाओं का एक समूह भी जनता दरबार में पहुंचा। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय समस्याएं महापौर के समक्ष रखीं। महिलाओं की प्रमुख शिकायत थी कि उनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब हैं और साफ–सफाई का कार्य नियमित रूप से नहीं हो रहा है। महापौर ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का दायित्व है कि शहर की हर गली और मोहल्ले में बुनियादी सुविधाएं बिना बाधा के उपलब्ध हों।महापौर ने अधिकारियों से कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को सुगम, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन देना है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए नागरिक सीधे अपनी समस्याएं रख सकते हैं।

बलरामपुर अस्पताल की ओटी में गिरने से मरीज की मौत

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में गिरने से मरीज की मौत हो गई। मरीज का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। परिजनों ने ऑपरेशन के दौरान गलत दवाई देने और घटना के बाद मामले को दबाए रखने का आरोप लगाया। घटना मंगलवार को बलरामपुर अस्पताल में हुई। मृतक की पहचान कश्मीरी मोहल्ला के मैदान एलएच खां निवासी 55 साल के बादशाह हुसैन के रूप में हुई। परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया। अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए। कश्मीरी मोहल्ला के मैदान एलएच खां निवासी बादशाह हुसैन (55) जरदोजी कारीगर थे। कुछ दिनों से उनकी आंखों में समस्या थी। डॉक्टरों ने मोतियाबिंद बताकर ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। वह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सोमवार को बलरामपुर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती हुए। उनके दामाद बहादुर शाह ने बताया कि सोमवार रात में ससुर को दो बोतल दवाई चढ़ाई गई। मंगलवार सुबह तीन बोतल दवाई चढ़ाई गई। वह सामान्य रूप से चल फिर रहे थे।

दवाई चढ़ने के बाद वह पेशाब करने गए।बहादुर ने बताया कि उसके बाद वह ससुर को ऑपरेशन के लिए आई ओटी लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर और स्टाफ ने ससुर को ओटी में कुर्सी पर बैठा दिया। उन्हें बाहर कर दिया। दामाद बहादुर शाह का आरोप है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर से धड़ाम से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। उन्होंने नर्स को भागते देखा तो पूछा कि क्या हुआ, लेकिन नर्स ने कुछ नहीं बताया। उन्हें ओटी के अंदर नहीं जाने दिया गया। इतनी देर में महिला नेत्र रोग डॉक्टर, चार–पांच नर्स और अन्य स्टाफ ओटी में अंदर भागते हुए पहुंचे। वह बाहर वेटिंग एरिया में ही दूसरे तीमारदारों के साथ बैठे रहे। करीब 10 से 15 मिनट बाद उन्हें बताया गया कि बादशाह कुर्सी से गिर पड़े थे। बहादुर ने बताया कि ससुर का चेहरा नीला पड़ा था। आंख सूज गई थी। डॉक्टर और स्टाफ ने मरणासन्न हालत में उनको चादर में उठाकर स्ट्रेक्चर से आईसीयू में पहुंचाया। इस बीच उनको सीपीआर दिया गया। मंगलवार रात में करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। बहादुर का आरोप है कि ओटी में गलत दवा आदि देने की वजह से ही ससुर की हालत बिगड़ी।

सुहेलदेव आर्मी ने काकोरी थाना घेरा, प्रदर्शनकारी बोले–बुजुर्ग को पेशाब चटवाने के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के काकोरी क्षेत्र में बुजुर्ग को पेशाब चटवाने के मामले में सुहेलदेव आर्मी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग को लेकर काकोरी थाने का घेराव किया। थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले में पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सुहेलदेव आर्मी संगठन के लोग पहले पीड़ित बुजुर्ग रामपाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उसके बाद थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। थाने के बाहर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।

संक्षिप्त

नगर आयुक्त ने एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण

संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बुधवार को जरहरा स्थित एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर के निर्माणाधीन ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की और कार्यों को तीव्रगति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पशु जन्म नियंत्रण से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स नगर निगम की प्राथमिकता में हैं और इनका समयबद्ध पूरा होना आवश्यक है।निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि जरहरा स्थित एबीसी ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शहर में आवारा पशुओं के नियंत्रण और उनके वैज्ञानिक देखभाल हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी शिकायत न हो।गोपाष्टमी के पावन अवसर पर नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार ने जरहरा स्थित राधा उपवन गौशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गौशाला में रह रहे गोवंशों को गुड़ खिलाया।

पंचायत सहायक करेंगे गांवों में बैंकिंग का काम, ग्रामीणों को घर बैठे मिलेंगी बैंकिंग सुविधाये

संवाददाता

लखनऊ। ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक गांव वालों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने का बड़ा माध्यम बनेंगे। इनके माध्यम से गांव के लोग कृषि लोन, गोल्ड लोन के साथ बैंकिंग से जुड़े अन्य काम करा सकेंगे।पंचायती राज विभाग पंचायत सहायकों को बैंकिंग करेस्पांडेंट यानि बैंक प्रतिनिधि का काम करने के लिए प्रशिक्षण दिला रहा है। एचडीएफसी बैंक के सहयोग से 210 पंचायत सहायकों को इसके लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है।

चरणबद्ध तरीके से राज्य के 57,694 ग्राम पंचायतों में तैनात सभी पंचायत सहायकों को बैंकिंग करेस्पांडेंट का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह के मुताबिक बैंकिंग करेस्पांडेंट के रूप में काम करने वाले पंचायत सहायकों को बैंकों की तरफ से कमीशन मिलेगा। पंचायत सहायकों द्वारा बैंकिंग का काम करने से गांव वालों को गांव के अंदर ही बैंकिंग सहुलियतें मिल जाएंगी।ग्रामीण लोन लेने के लिए सीधे पंचायत सहायक से संपर्क कर सकेंगे। पंचायत सहायक संबंधित बैंक से लोन स्वीकृत कराने के साथ ही बैंकिंग से संबंधित अन्य काम करेंगे। शुरूआत में लोन दिलाने और सावधि जमा जैसे काम दिए जाएंगे।बाद में जमा निकासी करने का काम लिया जाएगा।

उप्र सहित छह प्रान्तों के विद्युत वितरण निगमों को चेतावनी, संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के हर प्रारूप का होगा प्रबल विरोध

संवाददाता

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को हुई ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में उत्तर प्रदेश सहित छह प्रान्तों को चेतावनी दी गई है कि वे निजीकरण के तीन में से एक विकल्प को चुन लें अन्यथा उन्हें केन्द्र से मिलने वाली मदद बन्द कर दी जाएगी। 10 अक्टूबर को हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के जारी हुए मिनिट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित इन छह प्रान्तों के सामने पहला विकल्प यह होगा कि वे विद्युत वितरण निगमों की 51: इक्विटी निजी कंपनी को बेंच दे। ऐसी स्थिति में सरकार अरक्षणीय कर्ज (अनसस्टेनेबल डेट) का भार खुद उठा लेगी और निजी कंपनी के हिस्से में आए कर्ज के लिए 0: ब्याज पर 50 साल में वापस की जाने वाली वित्तीय सहायता देगी।दूसरे विकल्प के तौर पर इन राज्यों में विद्युत वितरण निगमों का प्रबंधन निजी क्षेत्र को दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार अरक्षणीय कर्ज (अनसस्टेनेबल डेट) का भार खुद उठा लेगी और निजी क्षेत्र के प्रबंधन को 5 साल तक वित्तीय ग्रांट दी जाएगी। तीसरे विकल्प के तौर पर इन राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां की स्टॉक एक्सचेंज में सेबी में लिस्टिंग की जाए। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनियां की ग्रेडिंग कम से कम श्एश् होनी चाहिए। ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों को जिनकी सेबी में लिस्टिंग हो जाएगी उन्हें भी भारत सरकार वित्तीय ग्रांट देगी।इन तीनों शर्तों को संघर्ष समिति ने निजीकरण के लिए ब्लैकमेल की संज्ञा दी है।संघर्ष समिति ने इस बात पर भी कड़ा एतराज जाहिर किया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन के पदाधिकारियों को क्यों बुलाया गया था और वे किस हैसियत से इस मीटिंग में सम्मिलित थे जिसमें निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय लिया गया ? संघर्ष समिति शुरू से ही इस बात का आरोप लगा रही है कि ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन का गठन निजी घरानों और सरकार के बीच में निजीकरण के लिए बिचौलिए की भूमिका के लिए किया गया है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोशिएशन को सरकार की मीटिंग में बुलाना संघर्ष समिति के इस आरोप की पुष्टि करता है। आज बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।

अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा, भाजपा सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं, दबाई जा रही पीड़ितों की आवाज

संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में दबंग और अपराधी तत्वों के मनोबल इस कद बढ़ गये कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव यादव ने बुधवार को कहा कि सत्ता के अहंकार में भाजपाई और सामंतवादी ताकतें किसान, नौजवान, महिलाएं सभी के साथ अन्याय कर रहीं है। संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब का नाम मिटाने का षड्यंत्र है। भाजपा उत्तर प्रदेश में तो किसानों पर अत्याचार कर ही रही है अन्य राज्यों, जहां उसकी सरकार है, वहां भी प्रताड़ित कर रही है। किसानों की जमीन और फसल छीनने की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुरखीरी हो या मध्य प्रदेश का गुना। भाजपा नेताओं द्वारा किये जा रहे जुल्म, ज्यादती, उत्पीड़न का तरीका एक जैसा है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों की आवाज दबाई जा रही है। भाजपाइयों की सामंती सोच में नारी का न तो कोई मान है और न स्थान है। भाजपा जनता को बरगलाने के लिए झूठे नारे देती है। महिलाएं और बेटियां समय–समय पर अपनी पीड़ा और भाजपा की सच्चाई समाज के सामने लाकर

इस सरकार की पोल खोलने का काम कर रही है।अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा प्रदेश में सामंतवादी तरीके से सत्ता संचालित करना चाहती है। भाजपा संविधान और कानून को नहीं मानती है। भाजपाई और उसके संगी साथी हर दौर में रूप बदल कर संविधान को हटाने और बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर का नाम मिटाने का प्रयास करते है। भाजपाई सोच बाबा साहब और उनके विचारों से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी और पीडीए संविधान और बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध है। क्योंकि संविधान हमारी ढाल है। संविधान ही संजीवनी है। उन्होने कहा कि जब संविधान का रक्षा कवच पीडीए के पास है तब भाजपा और उसकी सरकार इतना शोषण और जुल्म ढा रही है, अगर संविधान खतरे में पड़ा तो प्रभुत्ववादी किस हद तक अत्याचार करेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को बंधी उम्मीद

संवाददाता

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरि किशोर तिवारी व महामंत्री शिवबरन सिंह यादव द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से केन्द्रीय कैबीनेट द्वारा आठवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना का स्वागत करते हुए विलम्ब ले लिया जाने वाला सही कदम बताया है। कर्मचारी नेता इं. हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि जनवरी 2025 में केन्द्र द्वारा के वतन आयोग के गठन निर्णय लिया गया था किन्तु लगभग 10 आह बाद उसके गठन की अधिसूचना तथा आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्रीय कैबिनेट के निर्णय की सूचना के अनुसार यह आयोग सिर्फ केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तो के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा। जिसकी समय सीमा 18 माह होगी। हालाकि यह जनवरी 2026 से प्रभावी माना जायेगा। किन्तु इनमें केन्द्रीय कर्मचारियो के साथ पेंशनर्स का उल्लेख नही है, यह पूर्व के नोटीफिकेशन के अनुपालन के रूप में देखा जा रहा है। जिसके द्वारा दिसम्बर 2025 के उपरान्त अर्थात आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं दिये जाने की आशंका साबित हो रही है। कर्मचारी नेताओ ने केन्द्रीय सरकार से वेतन आयोग को पेंशनर्स से सम्बंधित संस्तुति को भी शामिल किये जाने की मांग की गई है।श्री तिवारी और श्री यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि आजाद भारत के बाद से कभी भी ऐसा नही हुआ है कि सेवारत कर्मचारियो, सेवानिवृत्त के लिए वेतन आयोगों (केन्द्र व राज्यो) द्वारा एक साथ विचारण नही किया गया हो। किन्तु ऐसा नही किया जाना एक बडे आन्दोलन के रूप में देखा जा सकता है।केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कें उपरान्त केन्द्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी संगठनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि का. शिवगोपाल मिश्रा के नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों के लिए आठवे वेतन आयोग के समक्ष टर्म्स आफ रेफरेन्स प्रेषित करते हुए केन्द्रीय वेतन आयोग से विचार किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए आयोग को विचारण करने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन ऐसा नही किए जाने से राज्य कर्मचारी अपने हक से वंचित रह जाएगें। परिषद के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नरेश कुमार ने आठवे वेतन आयोग के गठनका स्वागत करते हुए कहा कि महंगाई के दृष्टिगत अपनी रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करने की मांग की गई है। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने पूर्व की भांति जनवरी 2026 जब तक वेतन आयोग की संस्तुतियो को लागू किया जाय तब तक अन्तरिम राहत लागू दिए जाने की मांग की है। परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमकुमार सिंह, संयुक्त मंत्री अविनाश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, संयुक्त मंत्री विवेक कुमार उप महामंत्री अमिता त्रिपाठी, अशोक कुमार सिंह, सुभाषचन्द्र तिवारी, इं. डी. पी. सिंह, इं. श्रवण कुमार कुमार यादव,इं.राम सुरेश सिंह, पी.के. मिश्रा, अरूण कुमार सिंह आदि ने केन्द्रीय चुनाव आयोग से शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है।

भारत एमवे के दिल में है : एमवे के अध्यक्ष और सीईओ माइकल नेल्सन

अगले 3-5 सालों में एमवे इंडिया की प्रगति और बदलाव के लिए 100 करोड़ रुपये (12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश की घोषणा

बीएनई

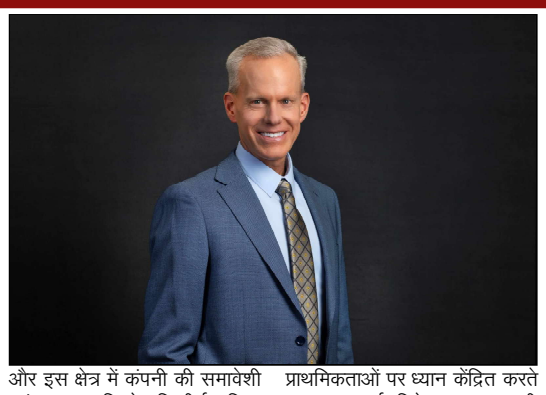

देहरादून। एमवे के अध्यक्ष और सीईओ माइकल नेल्सन ने कंपनी की विनिर्माण यात्रा के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सप्ताह भारत का दौरा किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो एमवे के वैश्विक संचालन में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करता है भारत, अमेरिका और चीन के साथ एमवे के केवल तीन वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक है। इस मजबूत नींव पर निर्माण करते हुए, कंपनी अगले तीन से पाँच सालों में 100 करोड़ रुपये (12 मिलियन अमेरिकी डॉलर') का निवेश करेगी ताकि एमवे बिज़नेस ओनर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्षमताओं को और मजबूत किया जा सके, अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार किया जा सके, और ग्राहक अनुभव को बढ़ाया जा सके। यह नेल्सन का भारत में अध्यक्ष और सीईओ बनने के बाद पहला दौरा है, जो एमवे की वैश्विक विकास रणनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है और इस क्षेत्र में कंपनी की समावेशी एवं सतत प्रगति के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराता है। माइकल नेल्सन, प्रेजिडेंट और सीईओ, एमवे ने कहा है कि भारत एमवे की वैश्विक दृष्टि के केंद्र में है,९। ष्यह अपनी डिजिटल रूप से सशक्त आबादी, गतिशील और युवा कार्यबल, और तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था से प्रेरित संभावनाओं का एक शक्तिशाली केंद्र है। एमवे के लिए भारत एक बदलाव के दौर में है और इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए, हम प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण निवेश करना जारी रखते हैं अपने मूल्यों और संस्कृति को मजबूत करना, उभरती उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद नवाचार में तेजी लाना, और शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप को गहरा करना। अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि और समग्र कल्याण पर बढ़ते फोकस के साथ, भारत हमारी वैश्विक वृद्धि का एक प्रमुख प्रेरक बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत की जीवंतता, विविधता, ऊर्जा और उद्यमशीलता की भावना एमवे के उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याण के माध्यम से लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करना से पूरी तरह मेल खाती है। जब हम स्थानीय विनिर्माण के एक दशक का जश्न मना रहे हैं, तो हमें अब तक की अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और आगे आने वाले असाधारण अवसरों से प्रेरणा मिल रही है। 100 करोड़ रुपये का यह निवेश एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्रित है। इसके तहत कंपनी अपनी भौतिक उपस्थिति का विस्तार करेगी और मौजूदा स्टोर्स को नए स्वरूप में विकसित करेगी, ताकि वे गतिशील सहभागिता केंद्र (डायनमिक एंगेजमेंट हब्स) बन सकें। इन केंद्रों में पुनः डिज़ाइन किए गए लेआउट, समर्पित प्रशिक्षण क्षेत्र, और बेहतर सेवा अनुभव शामिल होंगे। इसके अलावा, यह निवेश डिस्ट्रीब्यूटर्स को सशक्त बनाने पर भी केंद्रित रहेगा। इसके अंतर्गत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पाद ज्ञान, गुणवत्ता आश्वासन मानकों, और प्रमाणन प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्राहक जुड़ाव को मज़बूत किया जा सके और उद्यमशील सफलता को प्रोत्साहन मिल सके। एमवे इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश चोपड़ा ने कहा, "जैसे–जैसे भारत विकसित भारत 2047 की अपनी दृष्टि की ओर अग्रसर हो रहा है, हमें गर्व है कि हम इस परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान दे रहे हैं अपनी स्थानीय उपस्थिति को मज़बूत बनाकर और लोगों व नवाचार में निवेश करके। हमारे मूल्यों और संस्थापकों के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है यह उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने और समग्र कल्याण को सहयोग देने वाले विज्ञान–आधारित उत्पाद नवाचारों को आगे बढ़ाने के बारे में है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम राष्ट्र की प्रगति, आत्मनिर्भरता और एक स्वस्थ, अधिक सशक्त भारत की दृष्टि के साथ निकटता से जुड़ने का लक्ष्य रखते हैं।

कथित रूप से ओयो होटलों के दुरुपयोग की शिकायतें तेज

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। जनपद के तिर्वा, छिबरामऊ, सौरिख मार्ग, पाल चौराहा–रौनी रोड सहित कई इलाकों में ओयो ब्रांड के नाम पर संचालित कुछ होटलों के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन होटलों में संदिग्ध गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में असहजता का वातावरण बन गया है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत ने बताया कि पूर्व में भी ऐसी शिकायतों पर जांच के बाद कुछ होटलों को बंद कराया गया था। उन्होंने कहा कि अब पुनः शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई होटल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो तत्काल बंद कराया जाएगा। विधायक ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया है ताकि सभी होटलों की समीक्षा की जा सके। जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, ओयो सहित अन्य बजट होटलों की गतिविधियों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

एनसीएल में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

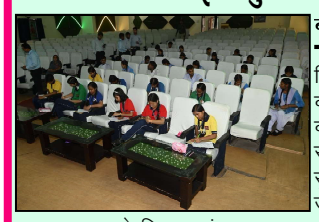

बीएनई

सिंगरौली। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) द्वारा बुधवार को स्कूली बच्चों के लिए 'साइबर सुरक्षा जागरूकता लेखन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करना था। बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हुए अपने लेखों माध्यम से साइबर सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार एवं ज्ञान का प्रदर्शन किया। एनसीएल साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत इस तरह के अनेक अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों, छात्रों और समाज के अन्य वर्गों में #CyberJagritBharat के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित करना है। इससे पहले एनसीएल ने कर्मियों के लिए एक क्विज़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था ।

शेयर बाजार में आईपीओ का बूम, 89 कंपनियों ने जुटाए 1.25 लाख करोड़, नवंबर में आएंगे दिग्गज इश्यू

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में उतार–चढ़ाव के बीच इस साल 89 कंपनियों ने आईपीओ बाजार से 1. 25 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें से अकेले अक्तूबर में 12 कंपनियों ने 38,300 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई हैं। महीने का अंतिम

इश्यू ओर्क्ला का होगा, जो 1,667 करोड़ का है। सेकंडरी बाजार में इस महीने अच्छी खासी तेजी रही और इसी आधार पर नवंबर में 40,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई गई है। स्टॉक एक्सचेंजों के मुताबिक, लेंसकार्ट का 7,700 करोड़ रुपये का आईपीओ नवंबर का पहला इश्यू होगा। नवंबर में जो बड़े आईपीओ आने वाले हैं उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल (10,000 करोड़), ग्रो (7,000 करोड़), बोट (2,000 करोड़) और पाइनलैब 5,800 करोड़ रुपये हैं। इनके अलावा फिजिक्सवाला 3,870 करोड़, प्रेस्टिज 2,500 करोड़ और पार्क मेडि भी इश्यू लाने की कतार में हैं। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस साल अक्तूबर और नवंबर में ही करीब 80,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है। दिसंबर तक कुल दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम कंपनियां जुटा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह अब तक का रिकॉर्ड होगा। आईपीओ के इतिहास में अब तक सबसे अधिक रकम पिछले साल 1.59 लाख करोड़ रुपये जुटाई गई थी। तब 91 कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी। हालांकि, हाल के दिनों में अगर एलजी के इश्यू को छोड़ दें तो बड़े आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एलजी का 11,600 करोड़ का निर्गम 52 गुना से ज्यादा भरा था और शेयर भी 50 फीसदी से ज्यादा भाव पर लिस्ट हुआ था। एसएमई रु 218 कंपनियों ने जुटाए रिकॉर्ड 9,449 करोड़ छोटी और मझोली यानी एसएमई कंपनियां भी पैसा जुटाने में पीछे नहीं हैं। इस साल जनवरी से अब तक इन्होंने बाजार से 9,449 करोड़ रुपये जुटाए। यह किसी भी साल में अब तक का रिकॉर्ड है। इस साल आए 93 निर्गम बढ़त के साथ लिस्ट हुए। 86 इश्यू गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुए। 174 कंपनियां जुटाएंगी 2.84 लाख करोड़ रुपये अगले कुछ समय में 174 कंपनियां 2.84 लाख करोड़ रुपये जुटाएंगी। इसमें से 90 को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। ये 1.30 लाख करोड़ जुटाएंगी। 84 ने 1.54 लाख करोड़ रुपये के लिए मसौदा जमा कराया है। अगले साल भी कंपनियां जमकर बाजार में उतरेंगी। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि आईपीओ लाने के लिए हर दिन कंपनियां भारी संख्या में मसौदे जमा करा रही हैं। अक्तूबर में करीब 60 कंपनियों ने सेबी के पास इश्यू लाने के लिए मसौदा जमा कराया है।

संक्षिप्त

म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, 10 जगह है गोलियों के निशान, शीशे टूटे

एजेंसी

करनाल, (हरियाणा)। अल्फा सिटी में स्थित म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर सुबह 5:00 बजे बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से तीन मंजिला भवन और मुख्य द्वार पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए। दीवारों सहित करीब 10 जगह गोलियों के निशान भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गोलियों के खोल

बरामद किए और साक्ष्य जुटाए। पुलिस की ओर से बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे बंगाली जा रहे हैं ताकि आरोपियों का सुराग लगे। इसके अलावा म्यूजिक कंपनी के प्रतिनिधि और भवन मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। सदर थाना के प्रभारी तरसेम ने बताया कि अल्फा सिटी में मकान नंबर 1244 में सागा म्यूजिक कंपनी के मालिक सुमित सिंह ने कार्यालय खोला हुआ है। बुधवार सुबह लोगों ने गोलियां चलने की आवाज सुनी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस टीम को मौके से गोलियों के कई खोल बरामद हुए हैं। फिलहाल धमकी या फिरौती मांगने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन फायरिंग को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

विश्वकप में जीतीं तो जैस्मिन–मीनाक्षी बनेंगी नंबर एक, निकहत हासिल करेंगी पुराना दबदबा

एजेंसी

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक के बाद से पूर्व विश्व चौंपियन निकहत जरीन (51) के लिए मुक्केबाजी के रिंग में वापसी आसान नहीं रही है। विश्व चौंपियनशिप में वह कोई कमाल नहीं दिखा सकीं, लेकिन अपने घर में होने जा रहा विश्वकप फाइनल्स सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि 2023 की विश्व चौंपियन स्वीटी के लिए भी वापसी का बड़ा मंच बनने जा रहा है। 14 नवंबर से ग्रेटर नोएडा शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में होने वाले इस टूर्नामेंट को निकहत और स्वीटी ने स्वर्णिम लक्ष्य बनाया है। स्वीटी तो दो वर्ष पूर्व विश्व चौंपियन बनने के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शिरकत करने जा रही हैं। वह भी अपने पुराने भार वर्ग 75 किलो में। इस टूर्नामेंट में मेजबान होने के नाते भारत पुरुष और महिलाओं के सभी 10–10 भार वर्गों में अपने मुक्केबाज उतारने जा रहा है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह की मानें तो हाल ही में लिवरपूल में विश्व चौंपियन बनने वाली जैस्मिन (57) और मीनाक्षी हुड्डा (48) अगर विश्वकप फाइनल्स में विजेता बनती हैं तो दोनों अपने भार वर्गों में दुनिया की नंबर एक मुक्केबाज बन जाएंगी। स्वीटी की दो साल बाद वापसी चोटिल लवलीना की जगह खेल रहीं स्वीटी कहती हैं कि 2023 में विश्व चौंपियन बनने के बाद उनके लिए दो साल उतार–चढ़ाव वाले रहे हैं। 75 भार वर्ग उनके लिए नया नहीं है। उनका वजन 76 से 77 किलो के आसपास ही रहता है, इसलिए वजन कम करने में परेशानी नहीं हुई। विश्वकप के जरिये वह फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने उतरेंगी। वहीं, निकहत कहती हैं कि यह टूर्नामेंट उनके लिए अहम है।

ट्रंप की टैरिफ नीति को सीनेट से झटका

ब्राजील पर लगाए शुल्क को हटाने से जुड़ा विधेयक पारित

एजेंसी

नई दिल्ली। रिपब्लिकन नेतृत्व वाली अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ मंगलावर को एक विधेयक पारित किया। इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ब्राजील पर लगाए गए भारी टैरिफ को रद्द करने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक उस राष्ट्रीय आपतकाल को समाप्त करेगा, जिसे ट्रंप ने जुलाई में घोषित किया था। उन्होंने यह कार्रवाई ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर कथित तख्तापलट के प्रयास मामले में चल रही सुनवाई के जवाब में की थी। विधेयक 52–48 के अंतर से पारित हुआ इस हफ्ते सीनेट में पेश होने वाले तीन टैरिफ बिलों में यह पहला विधेयक था। ब्राजील संबंधी प्रस्ताव 52–48 के मतों से पारित हुआ। पांच रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ समर्थन में मतदान किया। कनाडा और अन्य देशों पर लगाए गए ट्रंप के भारी टैरिफ को हटाने वाले विधेयक पर इस सप्ताह वोटिंग होने की उम्मीद है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने झूठे राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए व्यापार पर मनमाने फैसले लिए, जिनसे अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का भारी बोझ झेलना पड़ रहा है। प्रस्ताव के लेखक डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने कहा कि लोग परेशान हैं। राष्ट्रपित ट्रंप की नीति के कारण उन्हें खाने–पीने से लेकर कपड़ों, स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा तक सब कुछ महंगा पड़ रहा है। सीनेट का फैसले का पड़ा सकता है व्यापार वार्ता पर असर सीनेट ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ट्रंप मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया की पांच दिन की यात्रा पर हैं। गुरुवार को उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार वार्ता करने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने चेतावनी दी कि इस कदम से ट्रंप के नए व्यापार समझौतों पर असर पड़ सकता है। ब्राजील का दावा ब्राजील का दावा है कि बीते 15 वर्षों में अमेरिका को उसके साथ व्यापार से 410 अरब डॉलर का अधिशेष मिला है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति को खतरा बताने का तर्क दिया था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जो बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमे की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि बोल्सोनारो को लोकतंत्र खत्म करने की साजिश, हथियारबंद आपराधिक संगठन में शामिल होने और तख्तापलट की योजना बनाने का दोषी ठहराया गया है। उन्हें 27 साल की सजा सुनाई गई है, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस विधेयक का भविष्य हाउस की वोटिंग पर निर्भर अप्रैल में सीनेट ने कनाडा पर ट्रंप के टैरिफ हटाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन प्रतिनिधि सभा (हाउस) ने उसे खारिज कर दिया था। अब ब्राजील से जुड़े इस मसौदे का भविष्य भी हाउस में होने वाली वोटिंग पर निर्भर करेगा। हालांकि ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह सही परिस्थितियों में ब्राजील पर टैरिफ कम करने पर विचार करेंगे।

खालिस्तानी संगठन ने दिलजीत दोसांझ को दी धमकी! कॉन्सर्ट रद्द करने की मांग, जानिए क्या है बिग बी से कनेक्शन

एजेंसी

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन, सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने पंजाबी गायक–अभिनेता दिलजीत दोसांझ को धमकी दी है। इसके अलावा 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में गायक के होने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द करने के लिए कहा है। समूह का आरोप है कि सिंगर के कृत्य से 1984 के नरसंहार पीड़ितों का अपमान हुआ है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। ये 1984 दंगे के पीड़ितों का अपमान है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएफजे संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि दिलजीत दोसांझ ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति 17 में पैर छूकर 1984 के सिख नरसंहार के हर पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है। आगे संगठन ने आरोप लगाया कि अमिताभ ने 31 दिसंबर, 1984 में हिंदुस्तानी भीड़ को सार्वजनिक रूप से उकसाया था और खून का बदला खून का नारा लगाया था। इसके बाद पूरे भारत में कई सिख मारे गए थे। केबीसी 17 में पहुंचे थे दिलजीत दोसांझ हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिलजीत दोसांझ सेट पर पहुंचे थे और पहुंचते ही उन्होंने शो होस्ट–अभिनेता अमिताभ बच्चन के पैर छुए। बिग बी ने गायक को पंजाब का बेटा कहा, साथ ही दोनों एक–दूसरे के गले भी लगे। इसी के बाद से इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। आगामी कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग संगठन ने दिलजीत दोसांझ के आगामी कॉन्सर्ट को बायकॉट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है सिंगर ने स्मृति दिवस का मजाक बनाया है। साथ ही कहा कि यह उन पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए 1 नवंबर को गायक के होने वाले कॉन्सर्ट को रद्द करने के लिए कहा है। आपको बताते चलें कि 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर बरकरार रखना चाहेगी पांच वर्षों का वर्चस्व

एजेंसी

कैनबरा। टेस्ट हो या वनडे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी रहा है, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 में विश्व चौंपियन भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर अच्छा–खासा दबदबा रहा है। बीते पांच वर्षों से भारत टी20 में ऑस्ट्रेलिया पर लगातार श्रेष्ठता दर्ज करता आ रहा है। इस दौरान भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 सीरीज जीती हैं। सूर्यकुमार यादव की टीम जब बुधवार को मनूका ओवल में पांच मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी तो उसके सामने इस वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती होगी। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम को इस

सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का साथ मिलने जा रहा है। बुमराह को वनडे सीरीज में आराम दिया गया था। बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से निपटना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास भी इस सीरीज के जरिये अपनी खोई फॉर्म वापस हासिल करने का मौका होगा। सूर्यकुमार फॉर्म में जरूर नहीं हैं, लेकिन भारतीय टीम के बाकी क्रिकेटर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी भी शामिल है। हालांकि मुकाबला आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में खेलने का लाभ मिलेगा।

2047 तक देश को जहाज बनाने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल करना लक्ष्य, मैरीटाइम वीक में गडकरी

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत ने विश्व स्तर पर पांच जहाज निर्माण देशों में से एक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार जहाज निर्माण और मरम्मत को तेज गति से प्रोत्तसाहन दे रही है। मुंबई आयोजित मैरीटाइम वीक 2025 में बोलते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जहाजों के निर्माण और उसके मरम्मत के साथ हमारे लक्ष्य 2047 तक शीर्ष पांच जहाज निर्माण देश में से एक बनने का है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए एक वित्तीय संस्थान बनाने की जरूरत है, जो समुद्री उद्योग के विकसित करने और उसके गति को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता कर सके। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग एक ट्रिलियन डॉलर यानी 84 लाख करोड़ रुपये का है। यह क्षेत्र बंदरगाहों नौवहन और लॉजिस्टिक्स में निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743